International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 4, Issue 3, May.-June, 2024, pp: 94-102 www.ijhssm.org

उच्च शिक्षा प्रणाली में नई शिक्षा नीति 2020 की भूमिका

डॉ. अलका खन्ना (असिस्टेंट प्रोफेसर)
गिन्नी देवी मोदी इंस्टिट्यूट ऑफ़ एजूकेशन, मोदीनगर, गाजियाबाद

Date of Submission: 24-04-2024 Date of Acceptance: 02-05-2024

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र के अंतर्गत नई शिक्षा नीति 2020 की उच्च शिक्षा प्रणाली में क्या भूमिका है ? इसके विषय में शोधार्थी ने अध्ययन करने के पश्चात वर्तमान में भारतवर्ष की उच्च शिक्षा प्रणाली में समस्याएं, उस पर हुई चर्चा के मुख्य बिंदु, व उसकी सिफारिशें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का परिचय, विशेषताएं, उद्देश्य, सिद्धांत, उसका आगे आने वाले वर्षों में हमारी उच्च शिक्षा पर प्रभाव, इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश की है।

नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली के समावेशी और लचीले विकास का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को ग्लोबल मानकों के साथ समायोजित करना है, जिससे छात्रों की योग्यता और ज्ञान में वृद्धि हो। इस नीति में डिजिटल प्रौद्योगिकियों, नवाचारों, और अनुसंधान को प्रोत्साहित किया गया है तथा शिक्षार्थियों के लिए सहज और संवेदनशील उपकरण प्रदान किए गए हैं।

नीति का तैयारी के लिए विभिन्न स्तरों पर समाज से सहयोग लिया गया, जिसमें नागरिकों, शिक्षा अधिकारियों, और विशेषज्ञों के विचार और सुझाव शामिल किए गए। इससे नई नीति एक समग्र और एकीकृत शिक्षा दृष्टिकोण की कल्पना करती है, जिसमें कौशल विकास, बहु-विषयक शिक्षा, और रचनात्मकता को महत्व दिया गया है। नीति शिक्षा में गुणवत्ता प्रदान करने के लिए उपयोगी प्रौद्योगिकी और डिजिटल संसाधनों को भी प्रोत्साहित करती है।

इस नीति में विकलांग छात्रों, अल्पसंख्यकों, और अधिवासी छात्रों के लिए विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि शिक्षा के साथ सामाजिक समावेशन को भी प्रोत्साहित किया जा सके।

इस नीति में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए अधिक अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित किया गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के लिए संगठनों और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग भी बढ़ाया जा रहा है।

इस नीति के तहत शिक्षा की गुणवत्ता और प्रतिष्ठानों की प्राधिकृति को मजबूत करने के लिए शिक्षा अधिकारियों की प्रशिक्षण और प्रोफेशनल विकास को भी महत्व दिया जा रहा है।

इस नीति के अनुसार, शिक्षा प्रणाली में स्वच्छता, स्वास्थ्य, और पोषण के मामले में भी प्राथमिकता दी गई है, ताकि छात्रों की समग्र विकास में अवरोध न हो।

इस नीति में शिक्षा प्रणाली में अद्वितीयता और उच्चतम मानकों की भी प्राथमिकता दी गई है, ताकि छात्रों के लिए विशेष क्षेत्रों में विकास के अवसर उपलब्ध हों।

इस नीति का उद्देश्य है कि छात्रों को ग्लोबल मानकों के साथ अनुरूप बनाने के लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जोड़ा जाए।

नई शिक्षा नीति 2020 एक समृद्ध और समग्र प्रोग्राम है जो छात्रों के जीवन में न केवल शिक्षा की

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 4, Issue 3, May.-June, 2024, pp: 94-102 www.ijhssm.org

गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करता है, बल्कि उनके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास को भी मजबूत करने की कोशिश करता है।

नीति ने छात्रों के प्रभावी मूल्यांकन और प्रतिसाद के लिए नए मापदंड और तकनीकों को अपनाया है।

इसके अलावा, नीति में शिक्षा प्रणाली में गाइडेंस काउंसलिंग, मेंटरिंग और निर्देशन की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए भी बल दिया गया है।

यह नीति एक ऐसी अवसरों का संचारक है जो भारतीय शिक्षा प्रणाली को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए समर्थन प्रदान करता है, जिससे वह वैश्विक मंच पर अपनी विशेष पहचान बना सके।

बीज शब्द- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उच्चशिक्षा, भारतीय शिक्षा प्रणाली, शिक्षार्थी, शिक्षा पर प्रभाव।

प्रस्तावना

उच्चतर शिक्षा मानव समाज और सामाजिक कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से हम भारत को एक समर्थ, न्यायपूर्ण, सामाजिक रूप से सचेत, संस्कारवान और मानवीय राष्ट्रवादी बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। इसके साथ ही, उच्चतर शिक्षा राष्ट्रीय विकास में भूमिका निभाती है और युवा पीढ़ी को सामाजिक जागरूकता और समाजसेवा के महत्व को समझाती है। इसलिए, उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना राष्ट्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उच्चतर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि वह छात्रों को अच्छे, सजीव, बहुमुखी, और रचनात्मक व्यक्तित्व विकसित करे। इससे छात्र एक या अधिक क्षेत्रों में गहन अध्ययन करके सक्षम बनते हैं, और उन्हें नैतिक, सांस्कृतिक, और सामाजिक मूल्यों, विज्ञान, तकनीक, और विशेषज्ञता की 21वीं सदी की क्षमताओं का ज्ञान होता है। उच्चतर गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यक्तिगत उत्कृष्टता, रचनात्मक सोचने की क्षमता, सामूहिकता, और समाज में उत्पादक योगदान करने की क्षमता को विकसित करने का साधन बनती है। इसका उद्देश्य छात्रों को सकारात्मक और संतुष्ट जीवन और करियर भूमिकाओं के लिए तैयार करना है, और उन्हें स्वतंत्रता की भावना को प्रोत्साहित करना है।सामाजिक स्तर पर, उच्चतर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र को प्रेरित, सामाजिक रूप से सजग, जागरूक, और सक्षम बनाना है, जो अपने नागरिकों का उत्थान कर सके, और अपनी समस्याओं के लिए सही समाधानों को ढूंढ़कर लागू कर सके। उच्चतर शिक्षा विद्या मानकों और नवाचार का आधार भी बनाती है और इसके चलते राष्ट्रीय विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए, उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत रोजगार के अवसरों का सृजन करना ही नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य विवेकी, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े सहकारी समुदायों के साथ मिलकर एक समृद्ध, सामाजिक और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करना है।

वर्तमान में, भारत में उच्चतर शिक्षा प्रणाली की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं:

1. **गंभीर रूप से कम वेतन:** उच्चतर शिक्षकों की गंभीर रूप से कम वेतन के कारण उन्हें अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को नहीं निभाने में परेशानी होती है।
2. **भौतिक और आधारिक संरचना की कमी:** संशोधनात्मक कौशल और सीखने के संसाधनों की कमी उच्चतर शिक्षा के स्तर पर नीचे गिरा रही है।
3. **शिक्षा विधान का अभाव:** कुछ क्षेत्रों में शिक्षा का एक ही विधान होने के कारण, स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई का अभाव है।
4. **उच्चतर शिक्षा संस्थानों में गवर्नेंस की कमी:** कुछ संस्थानों में गवर्नेंस और नेतृत्व की कमी है, जो उनके विकास में बाधक है।
5. **प्रभावहीन शिक्षा प्रणाली:** कुछ मामलों में, शिक्षा प्रणाली प्रभावहीन हो गई है, जिससे छात्रों की उचित गति और अध्ययन में रूचि कम हो रही है।

6. **विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात:** अधिक संबंधित छात्रों के साथ, शिक्षकों का अध्ययन और प्रशिक्षण का प्रतिस्पर्धा और मानकों में कमी आ रही है।
7. **संबद्ध शिक्षार्थी-संघटना:** शिक्षार्थियों के अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए संघटनात्मक या व्यावसायिक मानकों की कमी है।
8. **अद्यावधिक स्तर का मानक:** अनेक उच्चतर शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम और मानक अद्यावधिक नहीं हैं, जिससे छात्रों को उचित दिशा और योग्यता प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

संसद के एक विशेष सत्र में शिक्षा पर, संसद की स्थायी समिति ने " उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन" को लेकर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इस रिपोर्ट में भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में इस प्रमुख नीतिगत बदलाव को लागू करने में प्रगति और चुनौतियों की समीक्षा की गई है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु उच्च शिक्षा संस्थानों की विविधता रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली का एक बड़ा भाग राज्य अधिनियमों के तहत संचालित होता है, जिसमें 70% विश्वविद्यालय इस श्रेणी में आते है। इसके अतिरिक्त, 94% छात्र राज्य या निजी संस्थानों में नामांकित हैं, केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकित छात्रों का अनुपात मात्र 6% है। यह उच्च शिक्षा प्रदान करने में राज्यों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

चर्चा के प्रमुख बिंदु

अनुशासनात्मक कठोरता:

पैनल ने विषयों के विभाजन में बरती जाने वाली सख्ती को लेकर चिंता जताई, जो अंतःविषय शिक्षा और नवाचार के लिये बाधक हो सकती है।

वंचित क्षेत्रों में सीमित पहुँच:

सामाजिक,आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तक पहुँच सीमित है, जिससे शैक्षिक अवसरों के समान वितरण में बाधा आती है।

भाषा संबंधी बाधाएँ:

स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या काफी कम है, जिससे संभावित रूप से आबादी का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा से वंचित रह जाता है।

संकाय व योग्य संकाय सदस्यों की कमी:

उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये सबसे प्रमुख बाधा बनती जा रही है, जिसका शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

संस्थागत स्वायत्तता का अभाव:

कई संस्थानों को स्वायत्तता की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे अनुकूलन और नवाचार करने की उनकी क्षमता में बाधा आती है।

अनुसंधान पर कम ज़ोर:

पैनल ने वर्तमान उच्च शिक्षा प्रणाली के अंदर अनुसंधान पर कम ज़ोर दिया ।

अप्रभावी नियामक प्रणाली:

उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाले नियामक ढाँचे को अप्रभावी माना गया, जिसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता थी।

मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट प्रोग्राम से संबंधित चिंता:

पैनल ने चिंता व्यक्त की कि भारतीय संस्थानों में MEME प्रणाली को लागू करना प्रभावी ढंग से संरेखित नहीं हो सकता है क्योकि यह सिद्धांत लचीला जरूर है किंतु इसमें छात्र प्रवेश और निकास अनिश्चित हैं । यह अनिश्चितता छात्र- शिक्षक अनुपात को बाधित कर सकती है।

सिफारिशें

- समान निधीकरण केंद्र एवं राज्य दोनों को उच्च शिक्षा में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों(SEDG) को समर्थन प्रदान करने के लिये पर्याप्त धनराशि आवंटित करनी चाहिये।

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 4, Issue 3, May.-June, 2024, pp: 94-102 www.ijhssm.org

- उच्च शिक्षा तक पहुँच में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु SEDG के लिये सकल नामांकन अनुपात के स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किये जाने चाहिये।
- लैंगिक संतुलन उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश हेतु लैंगिक संतुलन बढ़ाने के प्रयास किये जाने चाहिये।
- समावेशी प्रवेश और पाठ्यक्रम छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रवेश प्रक्रियाओं और पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाया जाना चाहिये।
- क्षेत्रीय भाषाओं और द्विभाषी रूप से पढ़ाए जाने वाले अन्य डिग्री पाठ्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- उच्च शिक्षण संस्थानों को दिव्यांग छात्रों के लिये अधिक सुलभ बनाने के लिये विशिष्ट कदम उठाए जाने चाहिये, जिनमें ढाँचा आधारित कदम महत्त्वपूर्ण हैं।
- सुरक्षित एवं समावेशी वातावरण सुनिश्चित करने के लिये भेदभाव- रहित और उत्पीड़न- विरोधी नियमों को सख्ती से लागू करने की सिफारिश की जानी चाहिये।
- विविधीकरण उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी(HEFA) को सरकारी आवंटन से परे अपने निधीकरण स्रोतों में विविधता लानी चाहिय।
- वित्त पोषण के लिये निजी क्षेत्र के संगठनों, परोपकारी फाउंडेशनों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी के विकल्प तलाशने चाहिये।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 भारत की उभरती विकास आवश्यकताओं से निपटने का प्रयास करती है। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों का सम्मान करते हुए, सतत् विकास लक्ष्य 4(SDG4) सहित 21 वीं सदी के शैक्षिक लक्ष्यों के साथ संरेखित एक आधुनिक प्रणाली स्थापित करने के लिये इसके नियमों एवं प्रबंधन के साथ शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव का आह्वान करता ह।
यह वर्ष 1992 में संशोधित(NPE1986/92) 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, का स्थान लेती है।

मुख्य विशेषताएँ

1. सार्वभौमिक पहुँच NEP 2020 प्री- स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा के सार्वभौमिक अभिगम पर केंद्रित है।
2. प्रारंभिक बाल शिक्षा 10+2 संरचना, 5+3+3+4 प्रणाली में स्थानांतरित हो जाएगी, जिसमें 3- 6 वर्ष के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा (Beforehand Childhood Care and Education-ECCE) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3. बहुभाषावाद कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, जिसमें संस्कृत और अन्य भाषाओं के विकल्प भी होंगे।
4. भारतीय सांकेतिक भाषा(ISL) को मानकीकृत किया जाएगा।
5. समावेशी शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों(SEDG) को विशेष प्रोत्साहन, विकलांग बच्चों के लिए सहायता और" बाल भवन" की स्थापन।
6. बाधाओं का उन्मूलन, इस नीति का लक्ष्य कला एवं विज्ञान, पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों तथा व्यावसायिक व शैक्षणिक धाराओं के बीच सख्त सीमाओं के बिना एक निर्बाध शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना है।

7. GER वृद्धि वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात को 26.3 से बढ़ाकर 50 करने का लक्ष्य 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ना है ।
8. अनुसंधान फोकस, अनुसंधान संस्कृति और क्षमता को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का निर्माण करना।
9. भाषा संरक्षण अनुवाद और व्याख्या संस्थान(IITI) सहित भारतीय भाषाओं के लिये समर्थन एवं भाषा विभागों को मज़बूत करन।
10. अंतर्राष्ट्रीयकरण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा और शीर्ष क्रम वाले विदेशी विश्वविद्यालयों का आगमन।
11. फंडिंग शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयास ।
12. परख मूल्यांकन केंद्र, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के रूप में परख(समग्र विकास के लिये प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) की स्थापना शिक्षा में योग्यता को आधार बनाने तथा समग्र मूल्यांकन करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
13. लिंग समावेशन निधि, यह नीति एक लिंग समावेशन निधि की शुरुआत करती है, जो शिक्षा में लैंगिक समानता के महत्त्व पर ज़ोर देती है और वंचित समूहों को सशक्त बनाने की पहल का समर्थन करती है।
14. विशेष शिक्षा क्षेत्र वंचित क्षेत्रों और समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विशेष शिक्षा क्षेत्रों की कल्पना की गई है, जो सभी के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच की नीति की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हैं।

नई शिक्षा नीति 2020 भारत में शिक्षा को बदलने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा है, जो महत्वपूर्ण सोच, समग्र विकास और वैश्विक दृष्टिकोण पर केंद्रित है।

नई शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020)

"नई शिक्षा नीति 2020" राष्ट्र के शैक्षिक प्रक्षेप पथ में एक परिवर्तनकारी कदम का प्रतीक है। आधुनिक युग की गतिशील आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए, यह नीति समग्र शिक्षा, डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास पर नए सिरे से जोर देती है। स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा के लिए नीति की तैयारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दायरे में आती है, जिसे भारत सरकार ने 2020 में अद्यतन किया। नई नीति में भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं।

नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य आकर्षण इसकी मजबूत रूपरेखा है, जो विभिन्न पृष्ठभूमि के विविध शिक्षार्थियों को पूरा करती है। स्थानीय मूल्यों में निहित वैश्विक नागरिकों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करके, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य भारत के शैक्षणिक परिदृश्य को नया आकार देना और सभी के लिए एक उज्जवल, अधिक समावेशी भविष्य सुनिश्चित करना है।

एनईपी दिशानिर्देश 2020:

मुख्य बिंदु

समग्र दृष्टिकोण: नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य छात्रों के समग्र संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है।

ईसीसीई पर जोर: प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा पर ध्यान हर बच्चे के लिए मजबूत बुनियादी शिक्षा सुनिश्चित करता है।

नई संरचना: एक संशोधित 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना अनुभवात्मक और कौशल-आधारित शिक्षा को एकीकृत करती है।

व्यावसायिक प्रोत्साहन: 2025 तक, 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्राप्त करने का लक्ष्य है।

क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता: एनईपी ग्रेड 5 तक क्षेत्रीय या घरेलू भाषाओं में शिक्षा को प्रोत्साहित करता है।

डिजिटल एकीकरण: DIKSHA जैसे तकनीक-संचालित प्लेटफार्मों को शामिल करने से सुलभ गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित होती है।

आकलन पर पुनर्विचार: योगात्मक से अधिक व्यापक, अनुकूली मूल्यांकन प्रणाली की ओर बढ़ें।

शिक्षक प्रशिक्षण: सतत व्यावसायिक विकास और प्रशिक्षण मॉड्यूल शिक्षकों को नई पद्धतियों के साथ संरेखित करते हैं।

समावेशिता और समानता: नई शिक्षा नीति 2020 सामाजिक-आर्थिक या भौतिक बाधाओं के बावजूद, सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य लक्ष्य भारत में शिक्षा के स्तर को वैश्विक स्तर तक ऊपर उठाना है, जिससे देश ज्ञान-आधारित उद्योगों में अग्रणी बन सके। यह उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लिखित शिक्षा के सार्वभौमिकरण के माध्यम से प्राप्त किया गया है। इसके लिए, सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पुरानी शिक्षा नीति में कई संशोधन लागू किए हैं, जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।

नई शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांत-

- प्रत्येक बच्चे की क्षमता को पहचानें और उसका विकास करें।
- बच्चों में साक्षरता एवं अंकगणित का ज्ञान विकसित करें।
- लचीले सीखने के विकल्प प्रदान करें।
- सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में निवेश करें।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास करें।
- बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ें।
- शीर्ष स्तर का अनुसंधान करें।
- सुशासन सिखाएं और बच्चों को सशक्त बनाएं।
- शिक्षा नीति को पारदर्शी बनाएं।
- टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दें।
- मूल्यांकन पर जोर दें।
- अलग-अलग भाषाएं सिखाएं।
- बच्चों की रचनात्मकता और तार्किक सोच का विकास करें।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभाव-

नई शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) 2020 ने दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ शैक्षिक परिदृश्य को फिर से परिभाषित किया है।

रटने से लेकर कौशल-आधारित शिक्षा तक एक उल्लेखनीय बदलाव महत्वपूर्ण सोच और समस्या-समाधान पर जोर देता है। नई शिक्षा नीति 2020 समावेशिता पर जोर देती है, यह सुनिश्चित करती है कि विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को समान अवसर मिले। स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों पर जोर देने के साथ, यह नीति छात्रों के लिए एक जड़ लेकिन वैश्विक दृष्टिकोण का वादा करती है। उन्नत शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल एक मजबूत मूलभूत आधार का वादा करते हैं, जबकि बढ़े हुए वित्तीय परिव्यय का लक्ष्य बेहतर बुनियादी ढांचे का लक्ष्य है। डिजिटल शिक्षा एक महत्वपूर्ण जोर हासिल कर रही है, जो छात्रों को तकनीक-प्रधान भविष्य के लिए तैयार कर रही है। एनईपी 2020 के माध्यम से , राष्ट्र समग्र, सार्थक शिक्षा का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

नई शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) कार्यान्वयन एवं समीक्षा समिति

मंत्रालय की योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक कार्यान्वयन और समीक्षा समिति

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 4, Issue 3, May.-June, 2024, pp: 94-102 www.ijhssm.org

स्थापित करने की है, जिसकी निगरानी उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी करेंगे। समिति नीति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होगी।

इसके अतिरिक्त, क्रेडिट बैंक प्रणाली और आईआईटी को बहु-विषयक संस्थानों में बदलने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इस योजना के कार्यान्वयन में देरी की स्थिति में, राज्य और जिला अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

5+3+3+4 संरचना क्या है?

5+3+3+4 संरचना नई शिक्षा नीति 2020 में पेश किया गया एक नया शैक्षणिक ढांचा है , जिसका उद्देश्य शिक्षार्थियों की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप पारंपरिक शिक्षण प्रणाली को बदलना और अनुकूलित करना है। यह मूलभूत शिक्षा, मध्य विद्यालयी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च विद्यालय चरणों पर जोर देता है। इस प्रणाली का लक्ष्य एक समग्र शैक्षणिक वातावरण बनाना है।

मूलभूत चरण (5 वर्ष)

पांच साल तक चलने वाले पहले खंड में बच्चे की शिक्षा के शुरुआती वर्ष शामिल हैं।

इसमें शामिल है:

3 साल की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, चंचल और गतिविधि-आधारित इंटरैक्टिव शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना।

अगले 2 वर्षों में ग्रेड 1 और 2 शामिल हैं, जिसमें मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर जोर दिया गया है।

प्रारंभिक चरण (3 वर्ष)

इस 3-वर्षीय चरण में ग्रेड 3 से 5 शामिल हैं। एक बहुआयामी शिक्षण दृष्टिकोण व्यापक शिक्षण अनुभव के लिए विषयों को एकीकृत करता है।

इस स्तर पर:

खोज और अन्वेषण पर अधिक जोर दिया जाता है।

पाठ्यक्रम समझ और अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए रटने की बजाय जटिल अवधारणाओं का परिचय देता है।

मध्य चरण (3 वर्ष)

यह खंड, जिसमें ग्रेड 6 से 8 शामिल हैं, विषय वस्तु पर गहराई से प्रकाश डालता है:

विषयों को अधिक विस्तार से खोजा जाता है, जिससे छात्रों को गंभीर रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षा शुरू की गई है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो।

माध्यमिक चरण (4 वर्ष)

अंतिम खंड, जिसमें कक्षा 9 से 12 शामिल हैं, छात्रों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए तैयार करता है, चाहे वह उच्च शिक्षा हो या व्यावसायिक मार्ग।

इन चार वर्षों के दौरान:

छात्रों को रुचि के विषय चुनने की छूट है।

वास्तविक दुनिया के कौशल और दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए समग्र विकास पर जोर दिया जाता है।

अतः 5+3+3+4 संरचना शैक्षिक ढांचे के पुनर्गठन की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यह सुनिश्चित करता है कि सीखना निर्बाध, एकीकृत और प्रत्येक शिक्षार्थी की विविध आवश्यकताओं के अनुकूल है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पहली बार 1986 में बनाई गई थी और 1992 में संशोधित की गई थी। इसके निर्माण को 30 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, जिसके दौरान दुनिया और समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

छात्रों को 21वीं सदी की मांगों के लिए तैयार करने के लिए शिक्षा क्षेत्र द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 शुरू की गई थी।

यह नीति एक परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से बनाई गई थी जिसमें विशेषज्ञ की राय, क्षेत्र के अनुभव, सार्वजनिक अनुसंधान, हितधारक की प्रतिक्रिया और बहुत कुछ पर विचार किया गया था।

नीति को एक पोर्टल पर अपलोड किया गया था, और हितधारकों और जनता से प्रतिक्रिया प्राप्त की गई थी।

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों को अपने विचार और टिप्पणियां देने के लिए आमंत्रित किया गया था।

नीति 22 भाषाओं में उपलब्ध कराई गई थी।

कई राज्यों में शिक्षा सचिवों के साथ बैठकें हुईं और शिक्षा संवाद हुए।

नई शिक्षा नीति 2024 पर सीएबीई की एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें 26 शिक्षा मंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, सीएबीई के सदस्य, संगठनों के प्रमुख और विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल हुए।

नई शिक्षा नीति 2024 को सरकार द्वारा सभी हितधारकों की प्रतिक्रिया और सुझावों के आधार पर लागू किया गया था।

एनईपी 2024 के तहत सार्थक योजना शुरू की गई। सरकार विभिन्न बदलावों को लागू करके शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हाल ही में सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉन्च की गई। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों के सर्वांगीण विकास के लिए सार्थक सार्थक योजना शुरू करने के लिए तैयार हैं।

योजना तैयार करते समय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे हितधारकों के विचारों, चर्चाओं और सुझावों पर विचार किया गया। शिक्षा मंत्रालय को कुल 7177 सुझाव प्राप्त हुए। नई शिक्षा नीति 2024 में 297 शिक्षा नीति सिफारिशें हैं जिन्हें समेकित किया गया है और निश्चित समय सीमा के साथ संबंधित एजेंसियों को सौंपा गया है। इन कार्यों को पूरा करने के लिए योजना में 304 आयाम भी शामिल हैं।

नई शिक्षा नीति 2024 की कुछ मुख्य बातें

- उचित प्रमाणीकरण के साथ उच्च शिक्षा के लिए एकाधिक प्रवेश और निकास बिंदु।
- विभिन्न निकास विकल्पों और प्रमाणपत्रों के साथ 3 या 4 साल के स्नातक पाठ्यक्रम।
- डिजिटल अकादमिक क्रेडिट को संग्रहीत और स्थानांतरित करने के लिए एक अकादमिक क्रेडिट बैंक का गठन।
- पाठ्यपुस्तकों पर निर्भरता कम करने के लिए ई-लर्निंग पर जोर।
- राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा की पेशकश कर रही है।
- 2030 तक हर जिले में एक बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थान बनाने का लक्ष्य।
- 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक बनाने का लक्ष्य।
- संपूर्ण उच्च शिक्षा (चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर) के लिए एकल निकाय के रूप में भारत का उच्च शिक्षा आयोग।
- भारत के उच्च शिक्षा आयोग के अंतर्गत चार कार्यक्षेत्र: राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद, सामान्य शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद।
- विकलांगों के लिए शिक्षा में बदलाव के साथ सरकारी और निजी शिक्षा के लिए समान व्यवहार।

निष्कर्ष

नई शिक्षा नीति 2024 एक बहुत जरूरी और व्यापक सुधार है, जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, लचीली और शिक्षार्थी-केंद्रित प्रणाली में बदलना है। नई नीति शिक्षा क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों और अंतरालों को दूर करने और सभी को उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के

बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

नीति एक समग्र और एकीकृत शिक्षा दृष्टिकोण की कल्पना करती है, जो कौशल विकास, बहु-विषयक शिक्षा और रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल संसाधनों के उपयोग पर भी जोर देता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

[1]. Chaturvedi, Amit (30 July 2020). "'Transformative': Leaders, academicians welcome National Education Policy". Hindustan Times. Archived from the original on 31 July 2020. Retrieved 30 July 2020. While the last policy was announced in 1992, it was essentially a rehash of a 1986 one

[2]. Kasturirangan-led panel to develop new curriculum for schools". indianexpress.com. 22 September 2021. Archived from the original on 16 October 2021. Retrieved 16 October 2021

[3]. Rohatgi, Anubha, ed. (7 August 2020). "Highlights | NEP will play role in reducing gap between research and education in India: PM Modi". Hindustan Times. Archived from the original on 9 August 2020. Retrieved 8 August 2020

[4]. National Education Policy 2020: Cabinet approves new national education policy: Key points". The Times of India. 29 July 2020. Archived from the original on 29 July 2020. Retrieved 29 July 2020

[5]. Kumar, Shuchita (31 July 2020). "New education policy: The shift from 10+2 to 5+3+3+4 system". Times Now. Archived from the original on 11 August 2020. Retrieved 9 August 2020

[6]. Free Entry- Exit Options Introduced For Students in NEP 2020". NDTV.com. Archived from the original on 7 May 2021. Retrieved 21 September 2020

[7]. Kumar, Manoj (29 July 2020). "India opens door for foreign universities under new education policy". Reuters. Archived from the original on 30 July 2020. Retrieved 31 July 2020